जी. एम. इंडियन बैंक

बनाम

आर. रानी एवं एक अन्य

दिसंबर 6, 2007

[बी.एन. अग्रवाल एवं पी.पी. नाओलेकर, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 366(25) और 342 - जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की जाति का सत्यापन - एक जिला स्तरीय समिति ने जाति प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया - परिणामस्वरूप, कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई - उच्च न्यायालय ने यह माना कि समिति का गठन **कुमारी माधुरी पाटिल** *के मामले के अनुसार नहीं था - समिति के आदेश और सेवा समाप्ति के आदेश को अभिखंडित कर दिया गया - उचित रूप से गठित समिति को नए सिरे से जांच करने के निर्देश पारित किए गए - अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय का आदेश न्यायसंगत है -* **कुमारी माधुरी पाटिल** *के मामले में दिए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश नहीं थे - सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र।*

उत्तरदाताओं को सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र के आधार पर बैंकों में नियुक्त किया गया था। बाद में, यह पाया गया कि उत्तरदाता उस विशेष समुदाय से संबंध नहीं रखते थे जिसका उन्होंने दावा किया था। एक जिला स्तरीय समिति ने जांच की और यह पाते हुए कि उत्तरदाता उक्त विशेष समुदाय से संबंध नहीं रखते थे, उनके प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया। उत्तरदाताओं ने जिला स्तरीय समिति के निर्णय को चुनौती दी। राज्य स्तरीय समिति ने इसे बरकरार रखा। इस बीच, उत्तरदाताओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उत्तरदाताओं ने जिला स्तरीय समिति के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने माना कि समिति का

गठन *कुमारी माधुरी पाटिल* के मामले* **में निहित निर्देशों के अनुरूप नहीं था। न्यायालय ने जाति प्रमाणपत्रों को अभिखंडित करने वाले समिति के आदेश और परिणामी सेवा समाप्ति के आदेशों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से गठित समिति को नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया। कर्मचारियों को बहाल करने के निर्देश पारित किए गए। अतः, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह तात्कालिक अपीलें दायर की गईं।**

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. *कुमारी माधुरी पाटिल* **के मामले में* न्यायालय ने जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए, उसमें उल्लिखित तीन अधिकारियों की समिति के गठन के निर्देश दिए थे।** *कुमारी माधुरी पाटिल* **के मामले में* प्रतिपादित कानून को इस न्यायालय की न केवल दो-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा, बल्कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी अनगिनत बार दोहराया गया था। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि** *कुमारी माधुरी पाटिल* **के मामले में* दिए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश थे।**

[कंडिका 6] [1029-बी-डी]

कुमारी माधुरी पाटिल और एक अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य, **[1994] 6 एस.सी.सी 241;** *कुमारी माधुरी पाटिल और एक अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, ठाणे और अन्य,* **[1997] 5 एस.सी.सी 437;** *बसंत बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य,* **जे.टी. (2000) 10 एस.सी. 280;** *निदेशक, जनजातीय कल्याण, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम लावेटी गिरी और अन्य,* **[1995] 4 एस.सी.सी 32 तथा** *सुधारक विट्ठल कुंभारे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य,* **[2004] 9 एस.सी.सी 481, पर भरोसा किया गया।**

1.2. इस न्यायालय के *******लावेटी गिरी* **के मामले के निर्णय के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि मसौदा नियमों को इस न्यायालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसके राज्य राजपत्र में प्रकाशन का निर्देश दिया गया है, लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि समिति के गठन के संबंध में** *कुमारी माधुरी पाटिल* **के मामले के निर्देशों को किसी भी तरह से संशोधित किया गया है।**

[कंडिका 7] [1029-जी-एच; 1030-ए]

निदेशक, जनजातीय कल्याण, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम लावेटी गिरी और अन्य, [1995] 4 एस.सी.सी 32, **का संदर्भ दिया गया।

1.3. चूंकि जिला स्तरीय समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा *कुमारी माधुरी पाटिल* **के मामले में प्रतिपादित कानून के उल्लंघन में था, इसलिए इस त्रुटि को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील में ले जाकर सुधारा नहीं जा सकता था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेशों और सेवा समाप्ति के आदेश को अभिखंडित करने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।**

[कंडिका 8] [1030-बी-सी]

1.4.यह दलील कि उच्च न्यायालय को बहाली का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था, पूरी तरह से इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ********सुधाकर विट्ठल कुंभारे* **के मामले में दिए गए निर्णय से तय है, जिसमें समिति के गठन में इसी तरह की त्रुटि के आधार पर, इस न्यायालय ने सरकारी कर्मचारी को तब तक बहाल करने का निर्देश दिया था जब तक कि मामला समिति द्वारा नए सिरे से तय नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार, इस दलील में कोई दम नहीं है। [कंडिका 9] [1030-डी-ई]**

****सुधाकर विट्ठल कुंभारे बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य,* **[2004] 9 एस.सी.सी. 481, पर भरोसा किया गया।**

1.5. राज्य सरकार द्वारा अब विधिवत गठित जिला स्तरीय समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार नए सिरे से मामले का निपटारा करे। [कंडिका 10] [1030- एफ]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार :2005 की दीवानी अपील संख्या 54।

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 2969/2002 में दिनांक 25.3.2003 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

के साथ

दीवानी अपील संख्या 2005 की 59-61, 55-57, 2006 की 50, 51, 2007 की 5661, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667 और 5668-5669।

उपस्थित होने वाले पक्षों के लिए आर. मोहन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राजू रामचंद्रन, एल.एन. राव, वी.के. राव, मधु सीकरी, साकेत सीकरी, सौरभ सुमन सिन्हा, रिशाद अहमद चौधरी, वी.जी. प्रगासम, जोसेफ अरस्तू, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, वी. विजयशंकर, एस. अरविंद, राकेश के. शर्मा, डी. वर्मा, सेंथिल जगदीशन और अपर्णा भट्ट।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया:

बी.एन. अग्रवाल, न्यायमूर्ति 1. विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इन अपीलों में निजी उत्तरदाताओं को अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरुद्ध बैंकों में नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्होंने स्वयं को कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य होने का दावा किया था, जो एक अनुसूचित जनजाति है। उनमें से अधिकांश को इंडियन बैंक द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। बाद में यह पता चला कि वे कोंडा

रेड्डी समुदाय से संबंध नहीं रखते थे, जिसके कारण एक जांच के आदेश दिए गए। यह जांच एक जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई जिसने पाया कि वे कोंडा रेड्डी समुदाय के नहीं थे और तदनुसार उनके पक्ष में जारी किए गए प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया गया। दीवानी अपील संख्या 54/2005 को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में निजी उत्तरदाताओं ने जिला स्तरीय समिति के उक्त निर्णय को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष चुनौती दी, जिसने अधिकांश मामलों में इसकी पुष्टि की, जबकि अन्य मामलों में मामले राज्य स्तरीय समिति के समक्ष लंबित रहे। इस बीच, जिला स्तरीय समिति के निर्णयों के अनुसार निजी उत्तरदाताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करने की आवश्यकता पड़ी, जिन्हें विभिन्न आदेशों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सभी मामलों में प्रमाणपत्रों को रद्द करने वाले समिति के आदेशों और सेवा समाप्ति के परिणामी आदेशों को अभिखंडित कर दिया गया है तथा यह निर्देश दिया गया है कि उचित रूप से गठित समिति के लिए कानून के अनुसार नए सिरे से जांच करना खुला रहेगा। कुछ रिट याचिकाओं में बहाली के निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले वेतन के भुगतान के संबंध में कुछ रिट याचिकाओं में यह निर्देश दिया गया है कि यह उचित रूप से गठित समिति द्वारा की जाने वाली जांच के परिणाम के अधीन होगा। दीवानी अपील संख्या 54/2005 में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जब अपील की गई, तो उसकी पुष्टि की गई; जबकि अन्य मामलों में कोई अपील नहीं की गई थी। अतः, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपीलें दायर की गई हैं।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलों के समर्थन में यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह मानना न्यायसंगत नहीं था कि समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा *कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य,* [1994] 6 एस.सी.सी 241 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार नहीं था,

क्योंकि समिति के गठन के संबंध में उसमें निहित निर्देश केवल दिशानिर्देश थे। यह भी तर्क दिया गया कि यदि जिला स्तरीय समिति के गठन में कोई त्रुटि थी भी, तो उस आदेश की पुष्टि राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई थी जो विधिवत गठित थी, इसलिए उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय का निजी उत्तरदाताओं को सेवा में बहाल करने का निर्देश देना उचित नहीं था।

4. हम सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या इस न्यायालय के *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश थे या इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानून थे। *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में उचित विचार-विमर्श के बाद न्यायालय ने विभिन्न निर्देश दिए थे। पृष्ठ 254 पर कंडिका 13 में निर्देश संख्या 4 इस प्रकार है:

> "4. सभी राज्य सरकारें तीन अधिकारियों की एक समिति का गठन करेंगी, अर्थात् (I) एक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव या संबंधित विभाग के निदेशक के पद से उच्च रैंक का कोई अधिकारी, (II) निदेशक, सामाजिक कल्याण/जनजातीय कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (III) अनुसूचित जातियों के मामले में एक अन्य अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन और जारी करने का गहरा ज्ञान हो। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अनुसंधान अधिकारी जिसे जनजातियों, जनजातीय समुदायों, या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों की पहचान करने का गहरा ज्ञान हो।"

5. उपरोक्त निर्देश संख्या 4 के अनुसार, जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए समिति तीन व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात (I) एक प्रशासनिक अधिकारी, (II) निदेशक, सामाजिक कल्याण/जनजातीय कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण, जैसा भी मामला हो, और (III) अनुसूचित जातियों के मामले में एक अधिकारी जिसे सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन और जारी करने का गहरा ज्ञान हो और अनुसूचित जनजातियों के मामले में, अनुसंधान अधिकारी जिसे जनजातियों, जनजातीय समुदायों, या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों की पहचान करने का गहरा ज्ञान हो। इसके बाद, उक्त निर्णय को वापस लेने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसे *कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय विकास, ठाणे और अन्य,* [1997] 5 एस.सी.सी 437 के मामले में निपटाया गया था और समिति के गठन में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

6. *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के निर्णय में दिए गए निर्देशों को निदेशक, *जनजातीय कल्याण, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम लावेटी गिरी और अन्य,* [1995] 4 एस.सी.सी 32 के मामले में दोहराया गया है, जिसमें दोहराते हुए यह टिप्पणी की गई थी कि भारत सरकार को इस मामले की अधिक विस्तार से जांच करनी चाहिए और इन मामलों के संबंध में एक समान कानून लाना चाहिए। *बसंत बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, जे.टी.* (2000) 10 एस.सी. 280 के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार नहीं था, इसलिए अपील स्वीकार की गई और यह निर्देश दिया गया कि इस न्यायालय के *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले के आलोक में समिति का गठन किया जाए और मामले का नए सिरे से निपटारा किया जाए। समिति के गठन के संबंध में *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के उक्त निर्देशों को इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *सुधाकर विट्ठल कुंभारे बनाम*

महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2004] 9 एस.सी.सी 481 के मामले में मंजूरी दी गई है, जिसमें चूंकि मामला *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त समिति को संदर्भित नहीं किया गया था, इसलिए अपील स्वीकार की गई और निर्देश दिया गया कि उचित रूप से गठित समिति मामले का निर्णय करेगी। पूर्वगामी चर्चाओं के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश थे। हमारी राय में, *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून को न केवल दो-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा बल्कि इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी बार-बार दोहराया गया है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के *निदेशक, जनजातीय कल्याण बनाम लावेटी गिरी और अन्य*, [1997] 4 एस.सी.सी 271 के मामले के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा समिति के गठन के संबंध में तैयार किए गए मसौदा नियमों को न्यायालय के समक्ष रखा गया था और इस न्यायालय ने राज्य सरकार को इसे राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। यह तर्क दिया गया था कि मसौदा नियमों के अनुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन छह व्यक्तियों से और जिला स्तरीय समिति का पांच व्यक्तियों से होना आवश्यक था और नियमों में यह उल्लेख किया गया था कि तीन व्यक्तियों की उपस्थिति समिति की बैठक के लिए आवश्यक कोरम होगी। जिला स्तरीय समिति में पांच सदस्यों में से, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी को एक श्रेणी में और दूसरी श्रेणी में मानवविज्ञानी का उल्लेख किया गया था। चूंकि तीन सदस्यों की उपस्थिति से कोरम बन जाता था, इसलिए यह तर्क दिया गया कि भले ही कल्याण अधिकारी और मानवविज्ञानी समिति में न हों, तब भी इससे इसका गठन अमान्य नहीं होगा। उक्त निर्णय के केवल अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि हालांकि मसौदा नियमों को इस न्यायालय द्वारा मंजूरी दी गई थी और

इसके राज्य राजपत्र में प्रकाशन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि समिति के गठन के संबंध में *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले के निर्देशों को किसी भी तरह से संशोधित किया गया है। स्थिति यह होने के कारण, हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के पहले तर्क में कोई सार नहीं दिखता।

8. जहाँ तक दूसरे तर्क का संबंध है, हमारी यह राय है कि चूंकि जिला स्तरीय समिति का गठन इस न्यायालय द्वारा *कुमारी माधुरी पाटिल* (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून के उल्लंघन में था, इसलिए इस त्रुटि को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील में ले जाकर सुधारा नहीं जा सकता था। स्थिति यह होने के कारण, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेशों और सेवा समाप्ति के आदेशों को अभिखंडित करने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को बहाली का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। यह बिंदु इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा *सुधाकर विट्ठल कुंभारे* (उपरोक्त) के मामले में पूरी तरह से तय किया जा चुका है, जिसमें समिति के गठन में इसी तरह की त्रुटि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा सरकारी कर्मचारी को तब तक बहाल करने का निर्देश दिया गया था जब तक कि समिति द्वारा मामले का नए सिरे से निर्णय नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार, हमें इस तर्क में भी कोई सार नहीं मिलता।

10. पूर्वगामी कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती, जिन्हें तदनुसार खारिज किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा अब विधिवत गठित जिला स्तरीय समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से छह महीने

की अवधि के भीतर कानून के अनुसार नए सिरे से मामले का निपटारा करे। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे. अपीलें खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।